Ministry of Home Affairs-Major Achievements, significant Development and important events for the month of April, 2019.

A meeting of the High Level Committee (HLC) was held under the Chairmanship of Hon'ble Home Minister on 15.04.2019 for Central Assistance to the States of Assam for flood/landslide of 2018.

2. On 28.02.2019, the union Cabinet approved the proposal for signing of a Memorandum of Understanding (MOU) between the National Crime Records Bureau (NCRB), India and the National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), USA regarding receiving of Tipline report on online child pornography and child sexual exploitation contents from NCMEC. The MoU was signed on 26.04.2019.

3. On 03.04.2019, Union Home Secretary reviewed the LWE scenario of the country with the Intelligence Bureau.

4. On 04.04.19, Union Home Secretary held a Video Conference with Additional Chief Secretaries (Home)/ Principal Secretaries (Home) of LWE affected states along with officers of implementing Ministry to review physical/ financial progress of 'Road Connectivity Project in LWE affected areas'.

5. In pursuance of Supreme Court's Order dated 14.03.2019, Home Secretary held a meeting on 26.04.2019 with the Chief Secretaries of Bihar and Jharkhand to discuss the issues of apportionment of pension liabilities between the two States.

6. Secretary (BM), MHA held a meeting on 10.04.2019 to discuss the proposal of Government of Assam for creation of e-Foreigners Tribunal and creation of 1000 additional Foreigners Tribunal.

7. A meeting to review implementation of provisions of A.P. Reorganization Act, 2014 was held by Special Secretary (CS) on 12.04.2019, with the representatives of all the concerned Ministries and both the State Governments.

8. Special Secretary (IS), MHA held a meeting with NSCN/K-Khango faction on 15.04.2019 at New Delhi. A new Ceasefire Agreement was signed for one year with NSCN/K-Khango faction w.e.f. 15.04.2019 to 14.04.2020.

9. Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of 4 Police Stations in the districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam have been declared as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 for a further period of six months w.e.f. 01.4.2019 to 30.9.2019 vide Notification No. S.O. 1494 (E) dated 01.04.2019.

10. Secretary (BM) held meetings of Security Related Expenditure (SRE) Standing Committee to finalize Annual Work Plans 2019-20 with Bihar, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Telangana, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Jharkhand, Maharashtra and Odisha, during the month.

11. An amount of Rs. 4.31 crore was sanctioned as ex-gratia compensation to the NOKs of CAPFs in 16 cases.

12. An amount of Rs. 25.05 crore was sanctioned for acquisition of land and Rs 118.95 crore was sanctioned for development of infrastructure to the CAPFs.

13. A total Number of 58 Coys of CAPFs were deployed in various States for Chaitra Navratra, Dr.BhimraoAmbedkarJayanti,for maintaining law and order duties during visit of VVIP at Prayagraj, Amroha, Ayodhya and other cities, Friday Prayer, Shab-E-Miraj, Shri Ramnavami, Shri Hanuman Jayanthi, Shab-E-Barat, Security of Parliament House.

14. On the recommendation of Election Commission of India a total of 24 coys of CAPFs were ordered for deployment in the states of Tamil Nadu, Goa, Karnataka in connection with Bye- Election related duties alongwith VII phase of General election to Lok Sabha, 2019.

15. Sanction for prosecution for filing the charge sheet against 19 accused persons was accorded under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for terrorist and anti-national activities.

16. During the month, Narcotics Control Bureau seized large quantities of heroin, ganja, opium, cocaine and other narcotics and arrested 28 persons including 05 foreign nationals in connection with drugs trafficking.

17. The President of India gave assent to 2 State Bills namely the Gujarat Ownership Flats (Amendment) Bill, 2018 and the Criminal Law (Gujarat Amendment) Bill, 2018 during the month.

18. Advisories were issued to the State Government / CAPFs to sensitize them on activities of Left Wing Extremists in the LWE affected areas.

19. CCTNS software has been deployed in 14841 Police Stations across the country and 14788 Police Stations are entering 100% FIRs through CCTNS.

20. Two days Data Users Conference for Census 2021 was held on 9-10th April, 2019 to take views of all stakeholders on various aspects related to Census.

****

अप्रैल, 2019 माह में गृह मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियां, महत्वपूर्ण घटनाक्रम एवं कार्यक्रम

वर्ष 2018 में आई बाढ़/भू-स्खलन से निपटने के लिए असम राज्य के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु दिनांक 15.04.2019 को माननीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई।

2. दिनांक 28.02.2019 को, केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एण्ड एक्सप्लाइटेड चिल्ड्रेन (एनसीएमईसी) से ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी और बाल यौन शोषण से संबंधित विषय-वस्तु के बारे में टिपलाइन रिपोर्ट प्राप्त करने के संबंध में राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) तथा एनसीएमईसी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया। समझौता ज्ञापन पर दिनांक 26.04.2019 को हस्ताक्षर किए गए।

3. दिनांक 03.04.2019 को, केन्द्रीय गृह सचिव ने आसूचना ब्यूरो के साथ देश की वामपंथी उग्रवाद संबंधी स्थिति की समीक्षा की।

4. दिनांक 04.04.2019 को केन्द्रीय गृह सचिव ने 'वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी परियोजना' की वास्तविक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा करने के लिए कार्यान्वयनकर्ता मंत्रालय के अधिकारियों के साथ-साथ वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के अपर मुख्य सचिवों (गृह)/प्रधान सचिवों (गृह)) के साथ वीडियो कांफ्रेंस आयोजित की।

5. माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 14.03.2019 के आदेश के अनुसरण में, गृह सचिव ने बिहार और झारखंड के बीच पेंशन संबंधी देनदारियों के विभाजन संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ दिनांक 26.04.2019 को बैठक आयोजित की।

6. सचिव (बीएम), गृह मंत्रालय ने ई-फॉरनर्स ट्रिब्यूनल सृजित करने और 1000 अतिरिक्त फॉरनर ट्रिब्यूनल के सृजन संबंधी असम सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए दिनांक 10.04.2019 को बैठक आयोजित की।

7. विशेष सचिव (सी एस) ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के प्रावधानों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों तथा दोनों राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 12.04.2019 को बैठक आयोजित की।

8. विशेष सचिव (आई एस), गृह मंत्रालय ने एनएससीएन/के-खांगो गुट के साथ नई दिल्ली में दिनांक 15.04.2019 को बैठक आयोजित की। एनएससीएन/के-खांगो गुट के साथ दिनांक 15.04.2019 से दिनांक 14.04.2020 तक एक वर्ष के लिए नए युद्ध विराम करार पर हस्ताक्षर किए गए।

9. अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में 4 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 01.04.2019 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1494 (अ) के तहत आगे और छः माह अर्थात दिनांक 01.04.2019 से 30.09.2019 तक की अवधि के लिए 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया है।

10. सचिव (बी एम) ने वार्षिक कार्य योजना 2019-20 को अंतिम रूप देने के लिए इस माह के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के साथ सुरक्षा व्यय संबंधी स्थायी समिति की बैठकें आयोजित कीं।

11. 16वीं मामलों में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के निकटतम संबंधियों को अनुग्रह मुआवजा के रूप में 4.31 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई।

12. केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को भूमि अधिग्रहण के लिए 25.05 करोड़ रुपए की राशि तथा अवसंरचना के विकास के लिए 118.95 करोड़ की राशि मंजूर की गई।

13. विभिन्न राज्यों में चैत्र नवरात्र, डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती, प्रयागराज, अमरोहा, अयोध्या तथा अन्य शहरों में अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने संबंधी ड्यूटियों, शुक्रवार की नमाज़, शाब-ए-मिराज, श्री राम नवमी, श्री हनुमान जयंती, शब-ए-बरात, संसद भवन की सुरक्षा के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कुल 58 कंपनियां तैनात की गईं।

14. भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर लोक सभा के आम चुनाव, 2019 के सातवें चरण के साथ-साथ तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक में उप चुनाव से संबंधित ड्यूटी के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कुल 24 कंपनियों को तैनात किए जाने का आदेश दिया गया।

15. आतंकवादी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत 19 अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल करने हेतु अभियोजन के लिए स्वीकृति प्रदान की गई।

16. इस माह के दौरान, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने बड़ी मात्रा में हेरोइन, गांजा, अफीम, कोकीन और अन्य स्वापक पदार्थों को जब्त किया तथा मादक पदार्थ के दुर्व्यापार के संबंध में 05 विदेशी राष्ट्रिकों सहित 28 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।

17. भारत के राष्ट्रपति महोदय ने इस माह के दौरान 2 राज्य विधेयकों अर्थात गुजरात स्वामित्व फ्लैट (संशोधन) विधेयक, 2018 और दाण्डिक विधि (गुजरात संशोधन) विधेयक, 2018 को सहमति प्रदान की।

18. राज्य सरकारों/ केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवादियों की गतिविधियों के बारे में अवगत कराने के लिए उनको परामर्शी-पत्र जारी किए गए।

19. पूरे देश में 14841 पुलिस स्टेशनों में सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर लगाया गया है तथा 14788 पुलिस स्टेशनों में सीसीटीएनएस के माध्यम से शत-प्रतिशत प्राथमिकियां दर्ज की जा रही हैं।

20. जनगणना से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में सभी स्टेकहोल्डरों की राय लेने के लिए दिनांक 09-10 अप्रैल, 2019 को जनगणना 2021 के लिए दो दिवसीय डाटा यूजर कांफ्रेंस आयोजित की गई।

****